Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

JULY
2023

9 Years of Seva

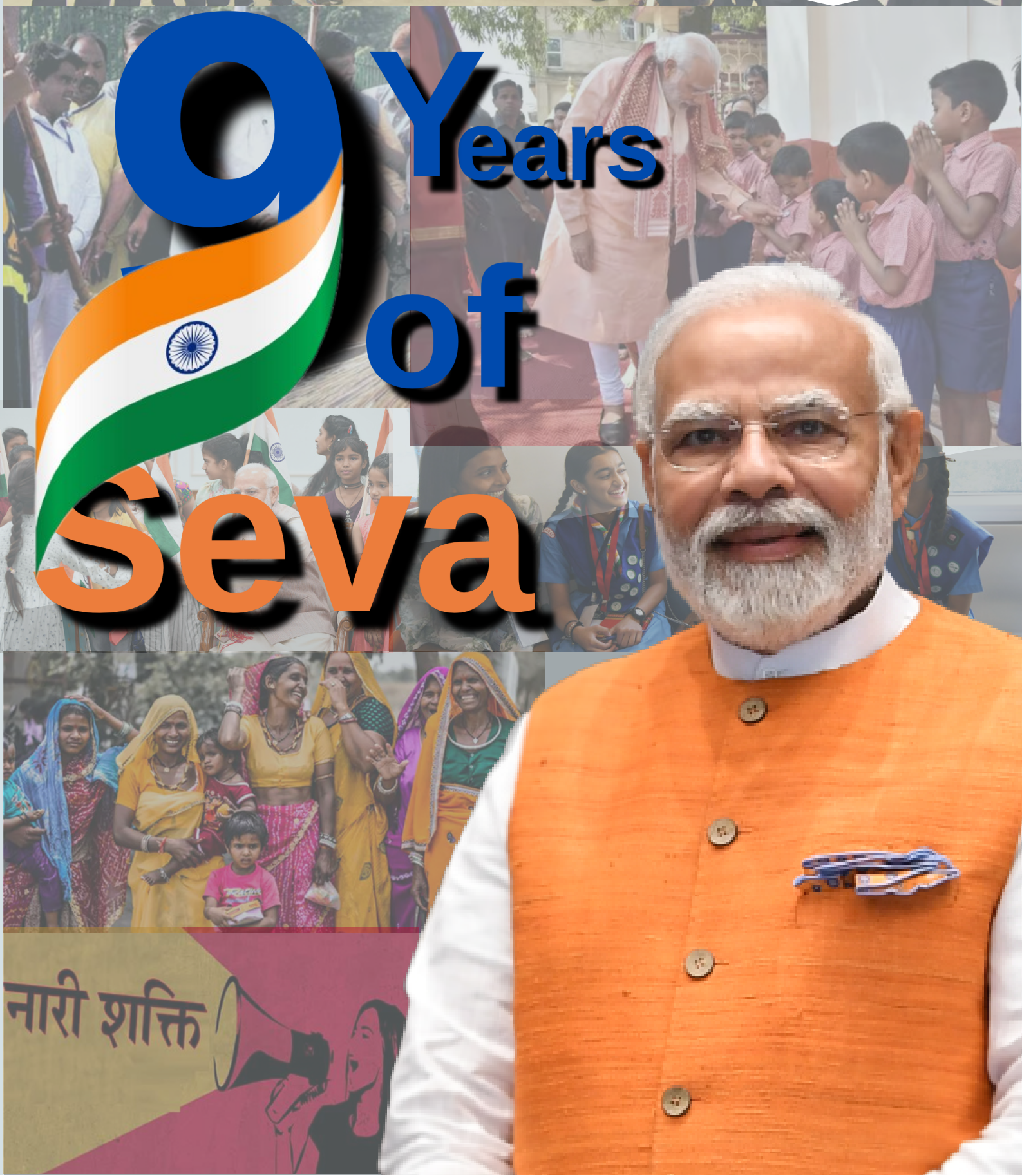

Research Team

Abhay Singh

Research Associate
Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Manujam Pandey

Research Associate
Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Utkarsh Mishra

(Intern)

Design

ANKIT

(Intern)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation
9, Ashoka Road,New Delhi-110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone : 011-69047014

भूमिका

वर्ष 2023 के मई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए. नि:संदेह यह नौ वर्ष समावेशी, प्रगतिशील, और सतत विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है. इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यधारा में ला दिया है और अब राजनीतिक संवाद एवं नीतिगत कार्य प्रक्रिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है.

2014 में प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद से श्री नरेन्द्र मोदी हर नीति निर्माण और इसे कार्यान्वित करने में 'भारत प्रथम' के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के अपने संकल्प पर अडिग रहे हैं. पिछले 9 वर्षों के दौरान सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव आया है. प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को तय करने और निर्धारित समय सीमा से पहले उन्हें पूरा करने में विश्वास रखते हैं. चाहे वह कोरोना का टीका हो, देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक निर्यात हो, पूरे भारत में हो रही डिजिटल क्रांति हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विद्युतीकरण, विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण, अथवा घरों तक पेयजल की सुविधा यह सारे लक्ष्य तय समय से पूर्व प्राप्त किए जा रहे हैं.

पूर्व में विकास के दिशाहीन दृष्टिकोण के विपरीत मोदी सरकार ने समग्र विकास की संस्कृति को अपनाया है जो समाज के सभी पक्ष को लेकर आगे बढ़ती है. यह ई बुकलेट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बुनियादी ढाँचे से होते हुए विदेश नीति तक भारत के परिवर्तन को दर्शाने वाला व्यापक संग्रह है. यह वंचितों की सेवा करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों को सम्मान दिलाने से जुड़ी 9 वर्षों की गाथा है. हम इस ई बुकलेट में अपना लेखकीय सहयोग देने के वाले सभी लेखकों का आभार व्यक्त करते हैं.

डॉ. अनिर्बान गांगुली
चेयरमैन - डॉ. श्यामा प्रसाद
मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

देश की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण

₹41,800 करोड़ से अधिक की राशि स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से की जा चुकी है स्वीकृत

98 athletes in TOPS Core Group & 182 in TOPS Development Group supported through TOPS Programme

14,500 schools to be upgraded and developed under the PM SHRI Yojana

9 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार ने 9 वर्षों के अपने शासन के दौरान प्रदान कीं

9.55 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर विगत 9 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खादी से सृजित

₹23.2 लाख करोड़ की राशि के 40.82 करोड़ से भी अधिक ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना MA के तहत स्वीकृत

23 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नौकरियां टेक स्टार्ट-अप द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के बीच निर्मित

Over 1.37 crore youth skilled under the PM Kaushal Vikas Yojana

78 crore new EPFO subscribers

मोदी सरकार में सुनिश्चित हुआ गरीबों का उत्थान - वंचितों का सम्मान

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज

11.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण आवास

स्वच्छ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण

पीएम स्वनिधि के माध्यम से 34.45 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मिला आर्थिक बल

मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के लिए मिले करीब 39.65 करोड़ लोन

2014 से पहले की तुलना में पांच गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत

वर्तमान में कें द्र में 60% मंत्री एससी, एसटी या ओबीसी हैं

117 आकांक्षी जिले विकास के मापदंडों पर आगे बढे

स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपये से अधिक का लोन

COVID लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

अन्नदाताओं का बदला जीवन
उन्नत हुई खेती, किसान हो रहे संपन्न

- 2013-14 की तुलना 2022-23 में कृषि बजट में 5.7 गुना वृद्धि
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये
- 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थी
- करीब २३ करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी
- वित्त र्वष 2013-14 से वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर-बासमती चावल निर्यात में 109.7 % की वृद्धि
- एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% की बढ़ोतरी
- एमएसपी पर दलहन खरीद में 7350% की वृद्धि
- 2022-23 में 2021-22 के मुकाबले कुल उर्वरक सब्सिडी 500% की वृद्धि
- 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपये कृषि लोन प्रदान किया जाएगा
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावोंं में 1.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निपटारा
- 2021-26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आवंट
- eNAM के माध्यम से अब 1260 मंडियां जुड़ी हुई हैं

मोदी सरकार का प्रण स्वस्थ बने जन-जन

आयुष्मान भारत के तहत 4.54 करोड़ अस्पताल घर

1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

2014 से अब तक कु ल 69,663 मेडिकल सीट जोड़ी गई

केंद्र सरकार द्वारा 1,500 से अधिक पीएसए संयंत्र स्वीकृत

एचडब्ल्यूसी के माध्यम से 15 करोड़ टेली-परामर्श

220 करोड़ से अधिक COVID वैक्सीन डोज दिए गए

मिशन इन्द्रधनुष द्वारा 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीको की सुरक्ष

37 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए

15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं

जन औषधि केंद्रों के कारण नागरिकों के लगभग 23,000 करोड़ रुपये बचे

9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र

3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसियों से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की

सांस्कृतिक संवर्धन का अमृतकाल

विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
और महाकाल प्रोजेक्ट

2020 में रखी गई
राम मंदिर की नींव

स्वदेश दर्शन
के तहत किए जा रहे
75 पर्यटन सर्किट विकसित

3.5 करोड़ रुपये की लागत से
सोमनाथ मंदिर
पुनर्निर्माण परियोजना

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक
अंततः वास्तविकता के धरातल पर

हृदय योजना
के तहत 12 हेरिटेज
शहरों का विकास

2014 से अब तक
231
चोरी हुई कलाकृतियां
भारत लाई गईं, 2014 तक
सिर्फ 13 वापस आई

207.3
करोड़ रुपये
की लागत से केदारनाथ
पुनर्विकास परियोजना

चार धाम एनएच
कनेक्टिविटी योजना
के तहत
889
किलोमीटर
के राष्ट्रीय राजमार्ग
विकसित किए जाएंगे

10 नए जनजातीय स्वतंत्रता
सेनानी संग्रहालय
स्थापित किए जा रहे हैं

PRASHAD योजना
के तहत सांस्कृतिक स्थलों
के विकास के लिए
1,586 करोड़
रुपये
का निवेश

सिख तीर्थयात्रियों
के लिए
करतारपुर
साहिब
कॉरिडोर
का उद्घाटन

बेहतर आज

उज्ज्वल कल

मध्यम वर्ग का जीवन हुआ सरल

7 लाख रुपये तक की आय तक फुल टैक्स रिबेट

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ से अधिक घर

2014 में मेट्रो 5 शहरों से बढ़कर अब (2023) 20 शहरों में पहुंची

इंटरनेट डेटा की कीमतें 97% घटी

UDAN योजना के तहत 1.16 करोड़ से अधिक लोगोंं ने सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठाया

4,355 शहरों को ओडीएफ का दर्जा

प्रभावी कर की दर 2013-14 में 19.22% से घटकर 2022 में 10.4% हो गई (15 लाख रुपये प्रति वर्ष)

उमंग ऐप के माध्यम से 21,801 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच

रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को फिर से चलाने के लिए स्वामी फंड के तहत 25,000 करोड़ रुपये

सीएलएसएस ने होम लोन के 59,048 करोड़ रुपये का बोझ कम किया

30 राज्ययों/केंद्र शासित प्रदेशों में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

12.90 करोड़ से अधिक डिजिलॉकर उपयोगकर्ता

नारी शक्ति को समर्पित

अमृतकाल

भारत में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाए

सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन

लिंगानुपात NFHS-4 में 991 से बढ़कर NFHS-5 में 1020 हुआ

2018-20 में मातृ मृत्यु दर घटकर 97 रह गई ह

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता

जन औषधि केंद्रों में 1 रुपये में 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए

3.18 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते खुल

9.6 करोड़ स्वच्छ ईंधन युक्त रसोई

करीब 2.5 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से 68.9% महिलाए

महिलाओ को मिले 27 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन

पेड मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह की गई

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3.94 करोड़ नि:शुल्क प्रसव पूर्व जांच

टेक्नोलॉजी विकास मे बढ़ता भारत

- भारत नेट के तहत 6.20 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर के बल बिछाई गई
- GeM पोर्टल पर 3.90 लाख करोड़ रुपये की रिकार्ड खरीद
- प्रति जीबी डेटा की कीमत 308 रु. से घटकर 9.94 रु. से भी कम
- पिछले 5 वर्षों में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता दोगुने से अधिक
- डिजिटल इंडिया के तहत 5.47 लाख कॉमन सर्विस सेंटर संचालित (सीएससी)
- डीबीटी के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत
- 2022 में दनिुया का 46% डिजिटल लेनदेन भारत में हुआ!
- 1.98 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर से जुड़ी
- देश भर के 669 जिलोंं में नए स्टार्ट-अप
- इसरो द्वारा एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए - एक अभूतपूर्वविश्व रिकार्ड
- मार्च 2023 में 868 करोड
- 2021 में भारत में 121 करोड़ मोबाइल सब्स्क्राइबर 79 करोड़ लोग करते हैं स्मार्टफोन का प्रयोग

सुनिश्चित किया समावेशी विकास

- सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
- महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया
- Rs 350 करोड़ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में श्रमिकों हेतु आवंटित राशि
- महान भील स्वतंत्रता सेनानी संत गोविंद गुरु जी को श्रद्धांजलि देते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 'संवैधानिक दर्जा' दिया गया

- 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर महीने मिल रहा है मुफ्त राशन

- 1.93 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया

- 45.32 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 24,606.36 करोड़ का ऋण वितरित

- 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली

पर्यावरण एवं विकास

- विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क (2,200 मेगावाट से अधिक) भादला, राजस्थान में शुरू
- उजाला योजना के तहत 36.86 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित
- 2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 2300% बढ़ी है
- नमामि गंगे मिशन के तहत 35,415 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं लाँच
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दोगुना से अधिक
- पीएम-कुसुम के तहत लगेंगे 35 लाख कृषि सोलर पंप

जम्मू और कश्मीर का पल्ली भारत का पहला 'कार्बन न्यूट्रल पंचायत' है

प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण परियोजना

भारत ने निर्धारित समय से 9 साल पहले COP 21 लक्ष्य हासिल कर लिया

2022 में बाघों की गिनती के अनुसार भारत में कुल 3167 बाघ है जो की एक रिकॉर्ड है

Nine Years of Renaissance: PM Modi's Crusade for a Better India

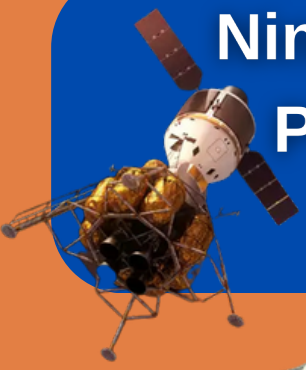

In 2013, India was named in the infamous list of Fragile Five Economies by Morgan Stanley that indicated the systemic risks emerging economies faced, owing to their disproportionately high level of dependence on foreign investments to sustain their growth. Not just that, by 2013, the overall investor confidence in India was terribly low owing to a severe phase of policy paralysis India was facing thanks to a dysfunctional government at the Centre, at that time, that was mired in innumerable cases of alleged corruptions. Further, a declining security environment owing to a spate of terror attacks India had faced over the previous one decade, often orchestrated from across the border but with no visible strong retaliation by Government of India, had further impeded India's reputation globally. It was indeed a tragedy that a country with enormous intrinsic potential, huge repository of natural resources and rich cultural heritage was severely falling short of expectations. It was then that Prime Minister Modi led NDA Government was elected to power in May 2014.

To understand the enormity of what has been achieved by Prime Minister Narendra Modi led NDA Government in the last nine years, one needs to look at the fact that in less than nine years, Modi Government elevated India from the list of Fragile Five to Major Five Economies of the world, with now India being the fifth largest economy of the world with a GDP of $3.75 trillion and is poised to become a $4 trillion economy by early next year.

Yet, it is not just that. The real accomplishment of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi is that India achieved this feat, along with breaching a record milestone of $770 billion of exports, and a robust foreign exchange reserve of nearly $590 billion, even when, much like the rest of the world, it went through a tumultuous time of a horrendous pandemic spread by Covid virus, followed by a devastating Ukraine-Russia war, both of which had a major impact on global supply chains and sky rocketed the price of many critical commodities.

In other words, India achieved these feats when the above-mentioned global catastrophes were ripping apart the world and pushed many countries on the brink of bankruptcy. India's phoenix like rise under Prime Minister Modi's leadership has been such an exceptional feat that India has been termed as 'a bright spot on this otherwise dark horizon' by global institutions such as IMF.

If achieving economic resilience was one part of the accomplishment, the other remarkable feat was invariably the manner in which India dealt and managed the Covid pandemic. From administering more than 200 crore dosage of 'Made in India's vaccines to over 100 crore of the eligible

citizens, entirely free of cost, and providing free additional rations to more than 80 crore people throughout the phase of pandemic, and still continuing, made sure that no Indian would be deprived of either the life-saving vaccines or basic food items, during those difficult moments of the pandemic. Under Modi Government, India exemplified the perfect template of public-private partnership wherein India's private sector made vaccines were being administered to the entire eligible population, completely financed by Government of India.

Further, at a time when most countries of the Western countries were reluctant to share their vaccines with the developing countries, Modi Government went out of the way to provide vaccines to more than 95 countries.
Also, if today India is being acclaimed for its economic resilience, one has to remember that India's economic resilience did not happen overnight but is the outcome of painstaking reforms ushered in by Modi Government over the last nine years.

From demonetization, to implementing of GST, which is one of the most significant structural reforms of the last three decades, to enacting Insolvency & Bankruptcy Code Act, to doing away with hundreds of redundant laws, to easing the process of compliance for organizations, in addition to major investments by Government of India to boost the country's infrastructure matrix, the list is indeed endless. Further, major efforts have also been put to improve overall productivity of economy through policies like National Logistics Policy and PM Gatishakti- National Master Plan for Multi Modal Connectivity. Also, not to forget the major impetus that was given by Government of India to boost the capital base of public sector banks and making them more resilient through mergers.

At a time when most other countries were grappling with challenges of dealing with pandemic related fallouts on the economy, and were try to take the easy way out through additional printing of money, PM Modi led Government of India, did not take any short cut. It is primarily because of this that when many other countries, from major ones to developing and marginal ones, are all grappling with challenges of financial bankruptcy, recession and high level of inflations, India remains relatively more resilient and stable because Modi Government, instead of taking short cuts, went ahead with more structural reforms that were aimed at making Indian manufacturing more competitive.

Modi Government's Production Linked Incentive (PLI) scheme spread across more than a dozen sectors, coupled with Atmanirbhar Bharat Abhiyan, made sure that India not only eventually emerges as a major hub for global manufacturing but also becomes a critical part of global supply chains. In areas of defence, a major initiative is being undertaken by Modi Government to reduce India's dependence on imports and eventually make India a major player on global defence industry by boosting indigenous production through availing more opportunities to Indian companies which in the past were always denied a level playing field, since middlemen and imports ruled the roost. PM Modi changed all of that. Also, Modi Government has taken some crucial decisions to simultaneously buy some critical high end weapon systems from abroad, since full-fledged self-reliance in defence production, even though desirable and the process has been started, would take time to fructify for high-end systems, and India needs to remain prepared for any eventualities in the immediate future. There is no contradiction in these two decisions and each complement the other.

Also, from making Article 370 inoperative to complete J&K's final integration with India, to conducting major cross-border strikes in the heart of terror dens across borders, to defying global sanctions to take oil and weapon systems from Russia, even while maintaining good relation with Western power blocks, PM Modi has always made sure that India's national interest comes before anything else.

It is astonishing that in a country where till 2013, it was a norm than an exception that a mere 15 paisa reached beneficiaries for every rupee allocated by Government of India under various welfare schemes, Modi Government's radical transformation of delivery of welfare schemes through JAM (Jandhan Aadhar Mobile) Trinity, which started with Jan Dhan Yojana to open more than 47 crore bank accounts, mostly for the unbanked, followed by connecting the same with Aadhar and mobile phone numbers, made sure that all kind of illegal intermediaries, and names of fake beneficiaries are wiped out, and money from government welfare schemes are directly transferred to the accounts of the real beneficiaries. A recent figure of Government of India stated that it saved $27 billion by application of DBT, as it eliminated all kinds of corruption by intermediaries.

From building more than 11 crore toilets and 2.23 lakh community sanitary complexes, to providing 40.82 crore loans worth Rs 23.2 lakh crore under MUDRA Scheme in the form of institutional funding to micro enterprises, hitherto unbanked, that also created crores of new generation of entrepreneurs, to creating the third largest ecosystem for startups in the world with more than 99,000 DPIIT recognised entities, to redefining public transport in India

with opening up of a series of new metro rail networks, along with new generation Vande Bharat Trains, Modi Government has set the ball rolling for India's journey towards becoming a $10 trillion economy in the coming one decade.

Not just that, so that India, unlike in the past, did not miss out on future opportunities, PM Modi has made sure that India takes the right kind of initiatives on mission mode basis to work on development of green hydrogen, deep space exploration, research on quantum computing and AI, as well as making India a hub for electric vehicle manufacturing. And unlike in the past, the most fundamental difference in terms of what PM Modi has strived to work is in taking into confidence the teeming millions of budding young entrepreneurs of the country by opening up avenues of opportunities for them so that not only they do not need to go abroad for fulfil their dreams in future, as was the norm in past, but also, so that their ideas can help India unleash the next generation of technologies from here as well.

Last but not the least, by giving equal focus on restoring India's rich cultural heritage, and by creating the right kind of connect between present day economic necessities along with research on technology for future, and guided by the essence of spirituality and cultural roots, PM Modi is making sure that India puts up a new template of development for future, which would not be merely for making money at any cost, but would be humane, and wealth generation would be rooted to greater good for not just a few but for nations and mankind as a whole.

Prime Minister Modi has sown the seeds of not just the revival of India's rich cultural heritage that had been tormented for centuries, and often ignored by successive regimes even after the country's independence, but is also making sure that India's real economic and technological potential is finally unleashed. It is for making sure that the work continues unhindered that the coming 2024 Lok Sabha Elections is so very crucial for India's future, to make sure that India becomes a $10 trillion economy in the next one decade and become the true voice and template for the developing world to follow.

Dr. Anirban Ganguly

Chairman - Dr. Syama Prasad
Mookerjee Research Foundation

‘मोदी मॉडल’ ने बदली देश की तस्वीर

मई 2023 में मोदी सरकार के नौ साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ सरकार ने आर्थिक कानूनों को पारदर्शी व सुगम बनाने की दिशा में गत नौ वर्षों में सफलता अर्जित की, वहीं दूसरी तरफ कल्याणकारी राज्य के रूप में लोकहित के ऐसे निर्णय भी लिए, जिनका जनता के हितों से प्रत्यक्ष सरोकार था। एकतरफ देश को आर्थिक मोर्चे पर कानूनी जटिलताओं से निकालने की दिशा में कानूनी सुधार करते हुए सरकार ने कदम बढाए तो दूसरी तरफ जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आवासीय योजना, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय एवं आयुष्मान योजना जैसे लोकहित के निर्णय लिए हैं।

देश की आजादी के बाद समाजवादी नीतियों की डगर पर चलते हुए कल्याणकारी राज्य की जिस अवधारणा का विकास हुआ, उसमें सरकारी योजनाओं में ‘लोकहित’ की बजाय ‘लोकलुभावन’ की नीति को ज्यादा तरजीह दी गयी। समाज की यह सामान्य मनोस्थिति है कि वह अपने दूरगामी हितों की बजाय तात्कालिक एवं आकर्षक दिखने वाली नीतियों के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है। चुनावी राजनीति का बुनियादी सच यह है कि इसके हितधारक राजनीतिक दलों की प्राथमिकता ‘री-इलेक्ट’ होने अर्थात चुनाव में जीतकर आने की होती है। यहीं से ‘लोक-लुभावन’ शब्द की प्रासंगिकता बढ़ने लगती है। मोदी मॉडल ने इस धारणा को बदला है।

अगर याद करें तो सितंबर 2014 में जापान की यात्रा पर गये मोदी ने वहां निवेशकों के साथ एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत में ‘रेड-टैप नहीं, रेड-कारपेट है।’ रेड-टैप को रेड-कारपेट में बदलने का कार्य मोदी के विजन में प्राथमिकता पर रहा होगा, तभी उन्होंने पद संभालने के महज चार महीने बाद विदेशी मंचों से यह कहना शुरू कर दिया था। हालांकि, यह बदलाव कर पाना कोई चुटकियों का काम नहीं था।

कानूनी सुधारों को अमली जामा पहनाने में कठिनाइयाँ थीं। लेकिन यह भी उतना सच है कि चाहें कड़वी दवा पिलानी पड़ी हो या लोकप्रियता के खोने का खतरा मोलना पड़ा हो, मोदी ने अपने दृष्टिकोण से समझौता नहीं किया। ऐसा करना उन्हें एक साहसी नेतृत्वकर्ता के रूप स्थापित करता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने विमुद्रीकरण का ऐलान किया। विमुद्रीकरण के लगभग आठ महीने बाद एक जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने अप्रत्यक्ष करों के सुधार की दिशा में 'एक राष्ट्र एक कर' के रूप में जीएसटी लागू कराने में सफलता हासिल की। जीएसटी को इसलिए भी सफल मानना चाहिए कि साल-दर-साल जीएसटी के तहत कर-संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल, 2023 में 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कर-संग्रह रहा है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के शुरूआती वर्षों में ही इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी तथा भगौड़ा आर्थिक अपराध विधेयक पारित किया। ये सारे निर्णय यथास्थितिवाद से टकराने वाले निर्णय थे। लेकिन सरकार ने इन निर्णयों को अमली जामा पहनाया। सरकार ने यह बात जनता को समझाने में कामयाबी हासिल की है कि उनके कार्यकाल में कोई भी उद्योगपति गलत ढंग से कर्ज नहीं लिया है तथा जिन्होंने पिछले यूपीए सरकार में कर्ज लेकर वापस नहीं किया, वे मोदी सरकार में खुद को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्हें देश छोड़ना पड़ा।

हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा इतने तक रूकने की नहीं थी, वे और आगे जाने का मन बनाकर आये थे। जनवरी 2018 में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि हम लायसेंस-परमिट राज को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में निवेश को सुगम बनाने के लिए हम लगतार कार्य कर रहे हैं।
अपने कार्यकाल के बेहद शुरूआती दौर में मोदी सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों तथा सरकार द्वारा किये गए कानूनी सुधारों का असर साफ़ तौर नजर आ रहा है। कारोबार में सुगमता की दृष्टि से भारत ने चमत्कारिक लक्ष्यों को छुआ है। वर्ष 2014 में 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत 142वें पायदान पर था, जो अब 63वें पायदान पर पहुँच चुका है। रैंकिंग में दिख रहा यह सुधार कोई आकस्मात हुआ परिवर्तन नहीं है बल्कि यह सुनियोजित प्रणाली के तहत उठाये गए क़दमों का परिणाम है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

दरअसल मोदी के इस दृष्टिकोण का आर्थिक पहलू तो परिणामों में नजर आ रहा है लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू थोड़ा अलग है। जब परम्परागत रूप से कोई स्थिति एक ढर्रे पर चली आ रही होती है तो सामान्यतया 'जोखिम' की तरफ जाना कोई नहीं चाहता। मोदी ने वो जोखिम लिया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनके जोखिम लेने के बावजूद लोकप्रियता की कसौटी पर उन्हें कोई नुकसान होता नहीं दिखा। चुनाव-दर-चुनाव उनकी लोकप्रियता और जनसमर्थन में बढ़ोतरी ही हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 2014 से भी बड़े जनादेश के साथ जीतकर आये। अनेक राज्य के चुनावों में भी प्रधानमंत्री मोदी का असर खूब दिखा है।

इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि मोदी लोकहित बनाम लोकप्रिय के नीति-निर्धारण में संतुलन स्थापित करने में सफल हुए हैं। साथ ही कड़े फैसले लेते समय लोगों के मन में यह भरोसा पैदा करने में भी उन्होंने सफलता हासिल की है, कि वे जो भी कर रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम लोकहित में हैं। दरअसल मोदी की इस सफलता के पीछे एक बड़ा कारण यह नजर आता है कि वे कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसका विजन और ब्लू-प्रिंट उनके मन में पहले से तैयार न हो। वे जानते थे कि आर्थिक सुधारों की कठिनाइयों से जनता को दो-चार होना पड़ेगा। इसलिए विमुद्रीकरण जैसा कड़ा फैसला उन्होंने तब लिया जब देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ चुके थे।

जनधन योजना से जो शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, वह आज भारत में पारदर्शी शासन का एक मॉडल बन रहा है। जनधन-आधार-मोबाइल की तिकड़ी ने डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को उनका लाभांश सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का व्यवस्थित और रिसावमुक्त तंत्र दिया है। सरकार और लाभार्थी के बीच अब बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आज देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर तीन महीने पर किसान सम्मान निधि बिना किसी अवरोध के पहुँच रही है। सब्सिडी आदि की राशि भी लोगों के बैंक खातों में बिना अवरोध के पहुँच रही है। अमृतकाल का भारत यह भरोसा करता है कि ऊपर से अगर 1 रूपया चलेगा तो नीचे भी 1 रूपया पहुंचेगा। बीच में कोई भी 85 पैसा नहीं हड़प सकता।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल में उपलब्धियां और चुनौतियाँ दोनों उल्लेखनीय हैं। इस दौरान कोविड जैसी वैश्विक महामारी की त्रासद भरी चुनौती से भारत मजबूती से लड़ा है। लॉक डाउन से लगाये स्वास्थ्य संरचना तक की चुनौतियों का डटकर सामना किया। कोविड के कठिन दौर में सरकार ने त्वरित और दूरगामी, दोनों तरफ कदम बढ़ाए। गरीबों को राशन दिया तो वहीँ स्वास्थ्य ढाँचे को रिकॉर्ड समय में सुदृढ़ किया। टेस्टिंग किट से लगाये वैक्सीन तक निर्माण करने में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। कोविड संकट का मुकाबला जिस तरह से मोदी सरकार ने किया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति न सिर्फ भारतियों के मानस पर बल्कि वैश्विक नजरिये पर भी असर डालने वाला रहा है।

मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए जो संकल्प तय किये थे, उनपर काफी काम किये हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने उन करोड़ों घरों में रसोई गैस पहुंचाने का कार्य किया, जिनके लिए यह एक सपना था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा था, वह अब उन गरीब बस्तियों में नजर आने लगा है जहाँ कुछ समय पहले तक झोपड़ियाँ नजर आती थीं। हर गाँव बिजली के बाद हर घर बिजली पहुंचाने की योजना चलाई तो इसे मुकाम तक पहुंचाया भी। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने के मामले में भी मोदी सरकार कामयाब होती दिख रही है। मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के नाम से शुरू स्वास्थ्य योजना के तहत लाभार्थियों के आ रहे आंकड़े मोदी की विश्वसनीयता पर मुहर लगाने वाले हैं।

ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के नौ साल के कार्यकाल में नीतियों के बीच विरोधाभास नहीं है बल्कि सभी नीतियां परस्पर पूरक की तरह देश के विकास में कारगर साबित हो रही हैं। अमृतकाल के भारत में 'पॉलिसी पैरालिसिस' की कहानी बीती बात हो चुकी है। अब देश नीति, निर्णय, नेतृत्व और नीयत हर मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

शिवानन्द द्विवेदी

लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर रिसर्च फैलो हैं।

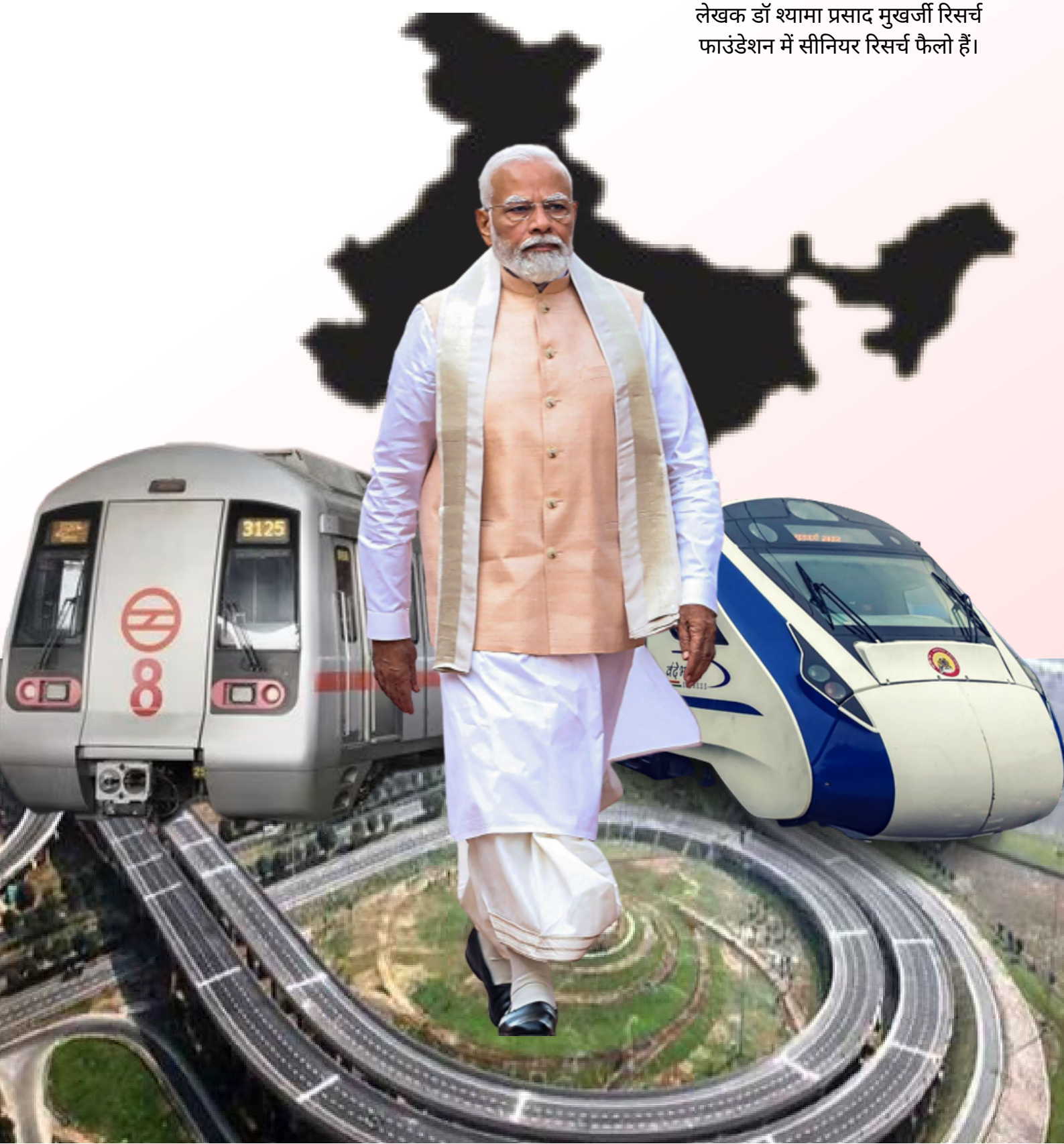

Beyond Renewables: How Modi Government Energised India's Moribund Coal Sector in Last Nine Years

For a country of India's size, and the challenges that it perpetually faces, having a pragmatic energy security architecture has always been of paramount importance. Since independence, as India meandered through difficult times from being an impoverished economy, almost being on the brink of a financial collapse in early nineties, and then eventually emerging, in a mere thirty years' time, as the fifth largest economy of the world, one thing that has perpetually bothered the policymakers of India, has been the domestic impact of volatility in the global energy markets, considering the disproportionately high level of dependenc india traditionally have had on imports of its energy requirements, especially crude oil and gas.

In 2014, when Prime Minister Modi came to power with a thumping majority, much like in many other sectors, which were facing systemic problems and policy paralysis, and were looking for solutions from the new regime, the energy sector too had a myriad of problems, and was hoping for a rescue mission.

The Paradigm Shift Since 2014

Much like in for other sectors, India needed a paradigm shift in thinking, and a new policy perspective to steer its energy sector, which still lacked a vision. India needed a new approach which would focus more on maintaining sectoral and institutional integrity for long term development of India, rather than continuing with populism for the sake of short-term vote gains. This was when Modi Government arrived.

Among many lobbies that worked against India's long-term interest, one of the prime ones, was the lobby that worked to reduce India's coal usage. There was this constant pressure from the Western countries to shun coal, even when for a country of India's proportion and population, shunning coal at one go was always going to create a multitude of problems, given the dependence that India had on thermal energy, and given the cost of procuring alternate fuel from international market.

Not the least was how 'environmental concern' was fast becoming a 'preferred barrier' for lobbies to impede India's developmental paradigm against which successive governments were found to be succumbing, and that resulted in innumerable key industrial projects in the past being abandoned, shelved or delayed.

For Modi Govt, The Task Was Cut Out

For Modi Government, if on one hand the challenge was to rationalise the issues of energy pricing and incentivise investments in the energy sector, the other was invariably to make sure that the seeds are sown for India's journey towards a major economy. That needed energy stability based on a pragmatic energy policy, and energy diplomacy of a new dimension. It was critical for Modi Government from the very onset to make sure that energy and environmental imperatives did not remain mutually exclusive, and that both can be taken care of, even while striving to meet the aspirations of India's 1.3 billion plus population.

The First Step: Managing the Coal Quagmire

In 2014, when Modi Government came to power, among many other issues, it had to deal with a major coal supply crisis that India's thermal based power sector was perpetually grappling with. It was indeed an irony that while India, by 2014, had more than 300 billion tonnes of geological resource of coal that was good enough to take care of India's requirements for more than 200 years, the country nevertheless continued to suffer from supply side problem of coal.

The crisis that had gathered pace for years was so profound that on most occasions, India was not even producing more than 160 gigawatts of electricity even when its installed capacity had touched the 250 gigawatts mark in 2014.

A FICCI report had quantified the economic loss, as a result of this power deficit, at $64 billion for 2011/12 . Most major thermal power plants had a precarious reserve of barely a few days of coal stock. A major part, if not the only part, of the problem was the sheer inability of Coal India to raise the quantum of annual mining of coal.

If the coal supply shortage crisis was not enough, the coal allocation scam, commonly called 'Coalgate', that allegedly happened during UPA era, did the rest in terms of making sure that the coal supply shortage crisis remained as it was.

Coal Swapping: A Simple Step to Solve a Gigantic Problem
For Modi Government, the coal supply problem was manifold but a start had to be made somewhere in terms of plugging the gaps. One of the first steps in that direction was approval that was given by Union Power Ministry for swapping the coal supply sources of power utilities run by Gujarat Government and NTPC. This was a major step towards rationalising the coal sourcing matrix of power utilities in the country, which was aimed at making sure that thermal power plants were allowed to source coal from the mines nearest to it. This had a manifold impact in terms of reducing the cost of transport, time taken for transport, and the eventual stock maintenance dynamics of thermal power plants.

While this was a simple solution to save time and cost for thermal power plants, the irony was that for long, power utilities of western India were allocated coal from mines in eastern India, while the plants in eastern India were getting coal linkages from coal mines in west and central part of India. And yet, no one before Modi Government had envisaged the idea of rationalising the coal linkages to reduce time, cost and overall power supply situation.

The particular swap in contention, namely the NTPC-Gujarat swap had a peculiar scenario wherein NTPC's power plants in Chhattisgarh were being fed by coal that was being imported and landed at ports in Gujarat, while the power plants run by Gujarat Government were fed from coal mined from the Korea Rewa mines in South Eastern Coalfields. A simple rejig by Modi Government made it possible to save money to the tune of Rs 400-500 crore.

In early 2015, a full-fledged coal swapping scheme was given approval by Government of India that initially included 19 power plants of state-run utilities like NTPC, DVC and a few states. Later, this scheme and its benefits were extended to private sector utilities and non-regulated sector as well. This indeed had a remarkable impact in terms of cost of power generation coming down due to supply chain efficiency.

Harnessing the SHAKTI Policy

The coal swapping policy was followed by another landmark policy initiative of coal linkage namely 'Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India' or SHAKTI.

The SHAKTI scheme in principle made sure that coal linkage facility for IPPs or the Independent Power Producers, became far more transparent, cost effective and convenient than what it used to be previously. The SHAKTI scheme had provision for coal linkage for both types of IPPs, one which has long term Power Purchase Agreement or PPA with state utilities, and the ones which did not yet have the same.

The coal linkage policy made sure that dependence of IPPs on expensive imported coal comes down, and drastically put to an end the previous ad hoc policy of discretionary allocation of coal. It also gave a fresh lease of life to considerable amount of stranded assets in the power sector which for lack of coal linkage was not in a position to become operational. The SHAKTI scheme therefore came as a relief for the banks as well, since a considerable amount of stranded assets in the power sector was now getting operational as a result of the SHAKTI scheme. Stranded assets result in rise in NPA or Non Performing Assets of banks. Operationalisation of stranded power plants was thus a big relief for those banks who had lent money for such projects

Auctioning of Coal: Bold, Transparent and Efficient

The third, and perhaps one of the most critical aspects of India's coal policy during the Modi era has been the coal block auction process that was started in June 2020, and made sure that some of the idiosyncrasies of the coal sector of India, were addressed.

India's rapid pace of development necessitated need for huge amount of electricity generation. The peculiarity of the Indian context was that India in spite of having one of the largest repositories of coal reserves in the world, was perpetually dependent on imports, so much so that it got the dubious distinction of being the second largest importer of coal in the world. While India was importing almost around 235 million tonnes of coal (2019), at a humongous cost of around Rs 1.71 lakh crore, interestingly, as per reports, almost around 135 million tonnes of additional coal could be additionally sourced from domestic sources, if India could enhance its annual production of coal.

This is precisely what the auction-based initiation of commercial mining was aimed at, since having a robust mining policy is the bedrock for any country's journey towards self-sufficiency and economic progress.

It was not that suddenly, as a result of the initiation of the auction process, India's coal import would come down. But as a step, it was one in the right direction, which over a period of time is expected to considerably reduce India's dependence on coal import, even as India's quantum of coal requirement would continue to rise.

The anomaly of India's underutilisation of its coal mining capacity was needed to be addressed in a transparent and pragmatic manner after the coal block allocation for captive mining by the previous regime was quashed by judiciary. After necessary amendments were made in the Mines & Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 and the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 became the basis for auctions for commercial mining.

The auctioneering process paved the way for intense competition among bidders and eventually this process was far more transparent and competitive than the method that was applied by the previous regime for coal block allocation. Eventually, liberalisation of India's coal mining sector was necessary just like it has been for several other sectors, for enhancing productivity, introduction of better technology, increasing revenue for the exchequer, and reducing dependence on the state-run monopolies in the sector. It also replaced the culture of multiple licenses by a policy of issuing single composite license, namely prospective license-cum mining lease.

The new policy also did away with the sectoral restrictions on usage of coal and gave freedom to coal miners to either use it for captive purpose, or sale to others. As per reports, India has so far auctioned and allocated 133 mines that have a combined capacity at peak level to the tune of 540 million tons per annum.

The above-mentioned policy initiatives could be summarised as creation of the regulatory policy framework that was comparable to the global benchmarks, and which was hitherto lacking in coal sector. Given the complexities associated with India's energy market, these were definitely stepping stones in right direction. However, the work was far from over.

Enhancing the Productivity of Coal India

Apart from the policy initiatives for the coal sector, one key area of focus, and the most critical one, was to enhance the productivity of Coal India Ltd.

A Press Information Bureau press release of 3rd May, 2023 states the following

India's overall coal Production has seen a quantum jump to 893.08 MT in FY 2022-23 as compared to 728.72 MT in FY 2018-2019 with a growth of about 22.6%. The priority of the Ministry is to enhance the domestic coal production to reduce the dependence on substitutable coal imports. In the last 5 years, the production of Coal India Limited (CIL) has increased by 703.21 MT (Million tonnes) as compared to 606.89 MT in FY 2018-2019 with a growth of 15.9%. SCCL has shown impressive growth at 67.14 MT in FY 2022-23 from 64.40 MT in FY 2018-19 with a growth of 4.3%. Captive and other mines have also taken a lead in coal production by 122.72 MT in FY 2022-23 from 57.43 MT in FY 2018-19 with a growth of 113.7%.

Ministry of Coal has initiated several measures to ramp up the domestic coal production to achieve self-reliance to meet the demand of all sectors and ensure adequate coal stocks at thermal Power Plants. The exceptional growth in coal production has paved the way for energy security of the Nation. The annual Coal Production target set for the FY 2023- 2024 is 1012 MT.

Source- Press Information Bureau

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1921662

Source- Press Information Bureau

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1921662

It is evident from the graphs that the efficiency of Coal India has indeed been enhanced in the last few years. The aim for the near and immediate future is to have a capacity to mine a billion ton of coal annually. Hopefully, a combination of an improved Coal India Ltd and expansion of private coal mining would eventually solve India's coal conundrum in the coming decade, when India's demand for energy would be at its peak to fuel an economy racing towards the $10 trillion mark by 2035.

Why it was a Big Deal to Reform the Coal Sector

One has to remember that even as India under PM Modi's leadership has made giant strides in the realm of renewable energy development as well, with India now having one of the largest installed capacities of renewable energy generation in the world, it was imperative for India not to give up on its coal usage since comprehensive transition to renewable energy development would take time and commensurate investments.

Also, from the standpoint of grid stability, thermal continues to be more stable than rest, and there was no reason for India to abandon usage coal because of pressure of western lobbies since the west has no legitimate authority to pontificate on environment, given what it has done for centuries in terms of degrading the same. While India remains conscious of its environmental responsibilities given its traditional and cultural ethos of conservation of nature, India's shift from coal to renewable has to be calibrated and gradual, so that it does not impact India's growth imperatives, considering that the country has to provide for the needs and aspirations of 1.4 billion people.

The irony however was that it was not the west but India's own policy paralysis of the past that impeded its optimal utilisation of its coal resources. It is from this perspective that the initiatives taken by Modi Government in the last nine years, in terms of ushering in structural reforms in the coal mining sector, can in certain ways be termed as a game changer.

While not much is discussed in mainstream media on the path-breaking reforms made in coal sector in the last nine years, and their resultant positive impacts, one simply cannot deny that the reforms initiated in the same are no less significant from the standpoint of setting the course to make India ready to fuel its quest to become a $10 trillion economy in the coming one decade. Credit for the same invariably goes to PM Modi led NDA Government, more so because it not only cleaned up the mess left behind in the sector by the previous regime, but also laid the foundation to unleash the true potential of India's coal mining sector through bold and visionary reforms.

Pathikrit Payne
Research Associate
Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9 साल का सफर 90 डिग्री बदलाव

जिस समय यह पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, सब ओर नए संसद भवन के उद्घाटन के चित्र छाए हुए हैं. मोदी पूजन में बैठे हैं, सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं. इन 9 सालों में भारत की जनता ने देखा कि मोदी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, और लोकार्पण भी. इसके पहले यह परंपरा नहीं रही. देश में लाखों शिलान्यास के धूल धूसरित पत्थर हैं जो दशकों से काम शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं.

मोदी ने इतना कुछ बदल दिया है कि विपक्ष हतप्रभ है, उसे पैर जमाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है. दुनिया की भारत को देखने की दृष्टि बदल चुकी है. मोदी स्वयं वैश्विक नेताओं की कतार में अग्रिम पंक्ति में सहजता से खड़े हुए हैं. दुनिया के ताकतवर नेता भारत के प्रधानमंत्री को “बॉस” कह कर बुला रहे हैं, उनका ऑटोग्राफ माँग रहे हैं, दुनिया के जटिल मामलों में हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहे हैं. कृतज्ञता से झुके नेता, पैर छू रहे हैं. देखने में लगता है कि इन 9 सालों में भारत की दिशा 90 डिग्री घूम गई है.

जब मोदी ने सत्ता संभाली थी, और पहला दौरा नेपाल का किया था, तब दुनिया ने देखा था कि स्वाधीन भारत में जन्मा भारत का पहला प्रधानमंत्री अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव को लेकर बेहिचक है. तब से विश्व योग दिवस, गंगा आरती, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास, नयी संसद का लोकार्पण से लेकर विदेशी मेहमानों को गीता भेंट करने की नई परंपरा तक यह स्थापित हो चुका है कि मोदी को अपनी जड़ों का गौरव है.

तुष्टिकरण से मुक्त, विकास और सुसाशन के मूल मंत्र के कारण, विपक्ष मोदी की बनाई नयी पिच पर खेलने को मजबूर है. इधर मोदी पर विपक्ष के आरोप लगते रहे, उधर भाजपा में दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व सामने आता गया. देश की राजनीति इस कदर बदली है कि कांग्रेस और अन्य कई दल दोबारा पैरों पर खड़े होते नहीं दीखते.

मोदी 'ट्रेंडसेटर' के रूप में उभरे हैं. मोदी कुर्ता, मन की बात, चाय पर चर्चा, स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रमाण हैं कि मोदी के स्पर्श से कोई भी अभियान, कोई भी चीज ब्रांड बन जाती है. शौचालय निर्माण , प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाते , स्वास्थ्य योजनाएँ, 1 रुपएमेंबीमाऔर डिजिटल लेनदेन ऐसी योजनाएँ हैं जिन्होंने भारत को सदा के लिए बदल दिया है.

डिजिटल लेन देन पर कभी चिदंबरम ने संसद में कहा था कि एक सब्जी वाला, एक खोमचे वाला डिजिटल लेनदेन कैसे करेगा? आज सब्जी वाले या खोमचे वाले को डिजिटल भुगतान करते हुए हमें ख्याल भी नहीं आता कि कुछ साल पहले ही यह अकल्पनीय था. 2014 से आज तक मोबाइल डाटा 30 गुना सस्ता हो गया है. मोबाइल उत्पादन नेट की रफ़्तार से त्वरित हुआ है. भारत में वंदे भारत रफ़्तार पकड़ रही है उधर साधन संपन्न देशों की रेलवे पटरियों पर भारत में बनीं रेलवे की बोगियां दौड़ रही हैं.

नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नई अवसंरचना और नई प्रक्रियाएं, इन चार आधारों पर 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अब उत्पादकों देशी-विदेशी निवेशकों की जुबान पर चढ़ गया है. ज़रूरत महसूस होने पर कुछ प्रमुख क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोला गया, रक्षा क्षेत्र में नीति को उदार बनाया गया और एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको) सीमाको 26% से 49% तक बढ़ाया गया. सावधानीपूर्वक केवल उच्च प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआईको अनुमति दी गई.

इसी तरह, रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं मेंनिर्माण, संचालन और रखरखाव में "स्वचालित मार्ग" के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई. बीमा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उदारीकरण मानदंडों को भी मंजूरी दी गई. इसके परिणाम भी चारों ओर दिखने लगे हैं. आधारभूत ढाँचा बेहद मजबूत हुआ. अब हम चार और आठ लेन वाली सड़कों के आदि हो गए हैं. बंदरगाह तेजी से ज्यादा से ज्यादा शहरों से तेज रफ़्तार वाली सड़कों के माध्यम से जुड़ रहे हैं. मोदी के पहले 70 सालोंमेंदेशमें 70 एयरपोर्ट बने, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के शासनकाल में 155 एयरपोर्ट बने.

स्टार्टअप यानेवो कंपनी जो पांच साल से अधिक समय से पंजीकृत नहीं है , जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़रुपयेसे अधिक नहीं है,जो प्रौद्योगिकी सेवा यया बौद्धिक सम्पदा के उत्पादों को बेचती है. 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना प्रारंभ हुई. तब के 442 स्टार्टअप्स साल 2023 में (28 फरवरी 2023 तक) 92,683 की संख्या को छू रहे हैं. यूनीकॉर्न अर्थात एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप. 108 यूनीकॉर्न की संख्या के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है.

सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति इन 9 सालों में बेहद मजबूत हुई है. मंदिर, ट्रेन, बस, बाज़ार में बम धमाकों के दौर 2014 मेंसमाप्तहो चुके हैं. भारत-पाक सीमा मामले में अब पाकिस्तान चिंतित है. सेना बंधन मुक्त हैं, गोली के जवाब में तोपखाना सक्रिय हो जाता है. दो सर्जिकल स्ट्राइक केवल आतंकियों पर नहीं दुश्मन फौज की मानसिकता पर भी हुई हैं. पाकिस्तान में बैठकर भारत में खुराफात करवाने वाले दुर्दांत आतंकी एक-एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं.

पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग पर मुश्कें कसी जा रही हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसे खून के आँसू रुला रहे हैं. चीन को डोकलाम और गलवान में दोहरा सबक मिला है. हिंद महासागर में भारत ने जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित बनाया है. इस बीच रक्षा उत्पादन इतिहास में शीर्ष पर है और भारत की रक्षा खरीद देखकर दुनिया अचरज में है. कहने की आवश्यकता नहीं कि मोदी के पिछले 9 साल चीन और पाकिस्तान को बहुत भारी महसूस हुए हैं. इन 9 सालों में भारत कई सौ कदम आगे आया है.

बिनय कुमार सिंह

लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर रिसर्च फैलो हैं।

Development with Democracy: How nine years of Modi Government is challenging long-held geo-political narratives

The last nine-years have seen a transformational shift for India in in economic and geo-political terms. Many foreign and some Indian commentators would reject the above statement as hyperbole. Some of them would grudgingly admit that Prime Minister Modi has indeed undertaken some very significant reforms and implemented large-scale developmental schemes successfully. But their unwillingness to acknowledge the true measure of these initiatives are due entrenched geo-political assumptions on the nature of democracy and economic development. Let me explain why.

Ever since Indian emerged as a free, democratic nation-state in 1947, western commentators have doubted the ability of a relatively poor, non-western country to be a democracy and undertake significant economic reforms to lift its millions out of poverty at the same time. The rise of authoritarian Asian 'tigers' like Korea and Taiwan in the 1970s, followed by China starting the 1980s, and the relative stagnation of India was seen as proof of this. China has indeed been the main counterpoint.

The accepted narrative has been that authoritarian China has been successful in delivering economic growth, and more importantly delivering the fruits of that economic growth in terms of better quality of life, infrastructure and opportunities for most of its citizens. This is in contrast with India, where a democratic system, though theoretically more able to holds its rulers accountable to the needs of its common citizens, failed to do so for decades after independence.

Western economic and political stakeholders had a vested interest in providing legitimacy to this narrative of Chinese state-led success. The Chinese market with its millions of middle-class consumers was a force to reckon with, and China was increasingly a vital cog in the wheel in the global value-chains dominated largely by western (and Japanese) multi-nationals.

This narrative of success of the Chinese state (and in contrast the failure of democratic India) had three vital components. These were:

1.Economic efficiency: The state successfully delivered large-scale infrastructure required for rapid economic growth, and ensured ease of doing business that led to investment, industrialization and job creation.

2.Effective delivery of socio-economic benefits: The state ensured that the fruits of economic growth reached a wide section of society. There were significant improvements in the quality of health and education services, low-cost public housing, public transport and other civic amenities.

3.Effective management of provincial governments: The party encouraged competition among states for investments and economic opportunities, while at the same time ensuring adequate control over provincial governments to effectively implement government led programs.

In light of these successes, it was easy to cast democratic India has a relative failure. But for the brief period under Prime Minister Vajpayee, infrastructure development seriously lagged behind economic needs. Ease of doing business was never a genuine priority, and a combination of red-tape, poor governance and sub-par infrastructure made India relatively unattractive as an investment destination.

The quality of delivery of India's socio-economic infrastructure and social welfare schemes, especially for its low-income population was well below average considering the amount of money that was being spend. Corruption, poor management and lack of transparency were endemic problems, and there was very little original thinking in policy-making circles to undertake substantive reforms to address these systemic challenges. Even more incredibly, even after decades of independence millions of Indian still did not have access to some of the most basic amenities that citizens in other lower-middle income economies would take for granted. Access to toilets, piped water, electricity, and a decent public transport system in most of India's cities simply did not exist.

This failure was visible even in places where you would least expect to find it. There was a sense of shameful dereliction in India's public places. This author had spent hours sitting in the waiting rooms of the Ministries of Commerce, Finance, and Transport staring at peeling plasters in walls, leaking air-condition vents, mice under the sofas and dirty toilets in the corridors. This was in sharp contrast to the beautifully maintained chambers of high officials and ministers, who also had their own special toilets.

It was therefore not difficult to portray India as an imperfect democracy that had largely failed its citizens, where the electoral choice was somehow at the end of the day meaningless because the state continued to be mostly unresponsive to the aspirations of its millions. And it was feudal enough to not care and make public show how it took its common citizens for granted-the horrible dereliction of its railway stations, bus depots, airports, roads, hospitals and even waiting rooms in its corridors of power.

And then something changed in 2014. Prime Minister Modi came and started talking about toilets. Nobody perhaps realized then, but that was the beginning of a quite but radical shift that was going to upend this narrative of failure of India, and by extension the failure of democracy as a system in low-income societies.

The most important initiatives under Prime Modi starting in 2014 has been designed to address the systemic problems that had led to India's consistent under-performance over the years. These included:

1.Jan Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) trinity: JAM completely overhauled the system of delivery of social benefits and welfare programs, minimizing leakage, reducing the possibility of corruption and bringing in transparency. The money being spend by government was actually reaching the intended beneficiaries.

2.Design and effective delivery of massive social-welfare schemes and infrastructure: When Prime Minister Modi set ambitious targets, many observers, including this author, did not believe that they would be feasibly achieved in such a short period of time. But toilets have been built in most Indian homes, millions of homes have access to amenities like electricity and piped water. The world's largest public healthcare insurance system has been operationalized in the form of Ayushman Bharat. All Indian villages would have 4G connection by 2024, and most of them would have connectivity through broadband optical fibre (2.5 lakh villages already have!).

3.The achievements in the development of physical infrastructure are equally impressive. All Indian state capitals will have a railway link by 2024, and full electrification of our broad-gauge railway would be achieved by 2023 end. More roads have been built in the last 9 years than decades combined previously. Starting from almost nothing, India has one of the most extensive and fastest growing expressway networks of any country in the world. The speed of implementation for economic infrastructure, whether dedicated freight corridors or newer and more modern ports has been unprecedented. More than 20 Indian cities would have a working mass-rapid-transport system (MTS) by 2025.

Prime Minister Gati Shakti is a landmark program with few parallels globally in terms of ambition and scale of delivery, seeking to provide effective multi-modal connectivity to all Indian urban and industrial centres, power stations, mines, village mandis and social sector infrastructure like schools, hospitals, tourism and pilgrimage centres.

4.The success in the field of economic governance is making the world sit up and notice. From first day in office, the Prime Minister set a clear target. He wanted to reduce the time, complexity and hassle of doing business in India. He realized that such transaction costs hit the smaller entrepreneurs the most, the bigger firms being more able to 'manage' the system. That India's ranking in the World Bank's Ease of Doing Business indicator improved from a lowly 142 to 63 currently is an independent testimonial to the overall success of these reforms. But this is just the beginning. Digital initiatives like the National Single Window (NSW) that includes state government level governance reforms, and the Unified Logistics Information Portal (ULIP) that brings comprehensive sectoral focus on e-governance and transparency are being seen as global benchmarks in terms of the scope and scale of operations

5.Last but certainly note the least, Prime Modi effectively inculcated an eco-system of co-operative federalism, where state and centre worked hand in hand for the implementation of major social and economic initiatives.

The success of these major national programs in such a short-time, meeting the seemingly impossible targets set by the Prime Minister is the testimonial to the effectiveness of this co-operation. In India's federal system on ground implementation would have been impossible without having the states on board. But PM Modi also introduced an element of competitive federalism. He did this purely through what is called 'nudge' economics. By developing metrics for rankings of states, and making these metrics available to public though multiple digital mediums, and through effective communication, the Prime Minister brought the spotlight on performance of state governments, making them accountable to their people. States have since been compelled to push their own performance through improved governance, and actively compete for investments and infrastructure projects.

These last nine years have restored the dignity of the Indian citizen. After decades of being insulted by pictures of public defecation, derelict infrastructure, and lectures on its inability to deal with extreme poverty from global 'experts', India is finally claiming back its self-respect.

These reforms have therefore restored the confidence in our democratic system to deliver. The argument that you need authoritarian regimes to deliver on the promise of economic development and social welfare in lower income economies is no longer valid. And last nine years has also shown that one can build infrastructure, in scale and speed, without sacrificing the democratic rights of people over land or compromising on genuine civil society concerns on environment.

The entire narrative of authoritarian efficiency vis-à-vis democratic chaos in non-western low-income societies has been discredited by the last 9 years of Modi government. Nothing underlined that better than democratic India's pandemic response and its performance compared to both authoritarian states in developing societies and western democracies. Whether the pace and efficiency of vaccination, or responding the critical health emergencies, India should head and shoulders over the world, despite the sheer size of population it had to cater to.

And this brings us to why the last 9 years of socio-economic development represents a geo-political shift. Two meta-narratives that dominated the world for decades have been demolished. The first meta narrative was that democracy was largely suitable for well to do western societies. While never explicit, there was an ingrained element of racism here. The evolution of democracy was seen as largely a western experience, informed not just by higher levels of economic achievement, but also societal characteristics unique to western (and Christian) societies. Strands of this argument are found starting from Max Weber in the early 20th century to more recent popular writings of authors like Niall Ferguson.

The second meta-narrative is one that is being pushed by the Chinese state and its supporters in the west. The basic idea being that a combination of authoritarian government and market economy is a successful model for developing economies, with China being its best example. Authoritarian governments, as long as they work towards economic development and social improvement, have complete legitimacy.

Democracy, freedom of speech, and a rule of law based on a constitution that holds even the rulers accountable are 'western' imports not entirely suitable to the political eco-systems of Asia, Africa and other non-western countries. The two narratives complement and feed of each other.

The nine years of Prime Minister Modi has now established a third powerful narrative-that development is not only possible in a low-income democracy, it is indeed the only sustainable means of long-term socio-economic development. Only an open, democratic system allows for evolution of bottom-up economic and social policies that are genuinely reflective of peoples aspirations.

The economic shock of the pandemic, and opportunistic behavior of the Chinese state in bending rules of international trade to its advantage has created a sense of disquiet among western businesses. This has been extravagated by the way the Chinese state has dealt with foreign firms invested in China, and indeed large Chinese private firms. It has been made clear that there is no rule of law, no independent courts, the Party and State are in complete control. The same vested economic interests in the west are keen to de-link from China and are looking at India with renewed interest and enthusiasm.

Indeed, two critical underlying themes of the G20 Summit this year are India as a voice of the global south, and India as a mother of democracy. In combination, this is the third powerful geo-political narrative. The message is that Indian democracy is rooted in Indic traditions and that democracy is a not a monopoly or invention of the west. Democratic institutions evolved in India at a similar or even earlier times than Greece. As did ideas of corporate independence and objective corporate governance for business.

India is offering an alternative as a major global power. An alternative of democracy that is rooted in non-western local traditions, respectful of local sensibilities and culture, while at the same time committed to the principles of free electoral choice, free speech, and free enterprise based on rule of law.

Many are not comfortable with the rise of this third alternative narrative. Large sections of the western media are therefore trying to undermine both the performance of Indian democracy and the genuine socio-economic achievements of the Modi government. News anchors in CNN, NBC, BBC, Deutsche Welle etc. or the editorials in New York Times, Washington Post, Guardian or Le Monde never tire of repeating that human rights, democracy, rule of law, respect for women, free markets-all of these are 'western values'. Like any good propaganda, this is repeated as nauseam in many different and subtle ways. Any challenge to what is essentially a narrative of western civilizational and geo-political dominance will not be taken lightly.

It comes as no surprise therefor that there has been a spate of reports that have ranked India poorly on various rankings related to freedom and democracy. A number of articles and papers, often by so called 'eminent' economists and social scientists have questioned India's ability for sustained economic growth and social change. This is precisely the backlash that can be expected as democratic, low-income, multi-ethnic India rises as a major economic power in the world stage.

The last nine-years are but the first steps towards India re-claiming the goals it has started out with in that fateful midnight 75 years ago. To be a democratic and prosperous nation that is able to fulfill the aspiration of its millions. But it is also a major achievement in geo-political and strategic terms. The achievements of the last nine years give India the ability and legitimacy to offer an alternative vision to rest of the world. The G20 Summit later this year would provide the platform to present this vision. And the decades that will follow will be the time to consolidate our social and economic transition-the Amrit Kaal where India fulfills her tryst with destiny, this time wholly and substantially.

Dr. Pritam Banerjee
Senior Research Fellow with
Dr Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation.

दूरगामी सुधारों को लागू करने में कामयाब रही मोदी सरकार

इसे विडंबना ही कहेंगे कि कृषि प्रधान देश भारत में खेती-किसानी कभी फायदे का सौदा नहीं रही। हां, एक बड़ी आबादी का भरण-पोषण करने में वह जरूर सक्षम थी। लेकिन 1991 में शुरू हुई उदारीकरण-भूमंडलीकरण की नीतियों के तहत खेती की यह क्षमता भी कम होती गई जिससे वह घाटे का सौदा बन गई। इसके बाद अन्नदाता किसानों की आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया। सरकारों ने इस समस्या के समाधान के बजाए महानगरों को जोड़ने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाई जिससे पलायन को बढ़ावा मिला।

2014 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती को फायदे का सौदा बनाने में जुट गए। इसके लिए दीर्घकालिक उपायों की शुरूआत की गई ताकि खेती की लागत में कमी आए। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री ने कृषि उपज के विपणन-भंडारण-प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया ताकि उपज की बरबादी रूके और उपज की लाभकारी कीमत मिले।

रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल को रोकने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इससे देश में मिट्टी की गुणवत्ता जांच की एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत से न केवल पड़ोसी देशों को होने वाली यूरिया की तस्करी रूकी बल्कि उसकी क्षमता में भी बढ़ोत्तरी हुई। अब सरकार नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है ताकि देश यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बने।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार संस्थागत ऋणों में भरपूर बढ़ोत्तरी किया है।

2022 में सरकार ने 18.5 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया गया जो कि 2014 में मात्र 8.5 लाख करोड़ रुपये था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाजों को श्रीअन्न नाम दिया। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों भारत सबसे आगे है। जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम चक्र से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए मोटे अनाज उम्मीद की किरण जगाते हैं। यही स्थिति दलहनी-तिलहनी फसलों की है जिन्हें हरित क्रांति के दौर में अनुर्वर भूमियों पर धकेल दिया गया। इसी को देखते हुए मोदी सरकार गेहूं-धान के बजाए मोटे अनाजों और दलहनी-तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोत्तरी के साथ-साथ इनकी सरकारी खरीद का नेटवर्क तैयार कर रही है। उदाहरण के लिए 2014 से 2022 के बीच जहां गेहूं के एमएसपी में 47 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई हुई वहीं चना में 68 प्रतिशत, सरसों में 76 प्रतिशत, कुसुम में 85 प्रतिशत और मसूर में 95 प्रतिशत।

सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का अभियान शुरू किया ताकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम की जा सके और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आए। 2013-14 में सिर्फ 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण होता था जो कि अब 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सरकार ने पेट्रोल में दस प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पांच महीने पहले हासिल कर लिया। इससे किसानों को आठ वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। इससे उत्साहित सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाना था। इसी तरह मोदी सरकार कचरा व गोबर से बायोगैस-सीएनजी बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।

मोदी सरकार किसानों को फसल उत्पादन से आगे बढ़ाकर बागवानी, मछली पालन जैसी आयपरक गतिविधियों में शामिल करना चाहती है। इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है। इसी तरह किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना शुरू की गई है। सरकार के इन प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर के अनुसार खेती से होने वाली आय के स्रोतों में काफी विविधता आई है और अब वह केवल फसली खेती व पशुपालन तक सीमित नहीं है।

किसानों को प्रत्यक्ष नकदी समर्थन देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की गई है। इससे तहत 11.3 करोड़ किसानों को हर चौथे महीने 2000 रुपये की तीन किस्तों में हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर विपणन सुधारों पर है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई नाम) के साथ–साथ सरकार फल-सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के शीघ्र परिवहन हेतु किसान रेल व किसान उड़ान की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों से खाद्यान्न कारोबार पर मंडी शुल्क में एकरूपता लाने की सलाह दी है। इससे जिंस बाजार एकीकृत नहीं हो पाता है जिसका दुष्प्रभाव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर पड़ता है।

समग्रत: मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में खेती-किसानी में दूरगामी सुधारों को लागू किया ताकि खेती फायदे का सौदा बने और गांवों में कृषि आधारित उद्योग-धंधों की शुरुआत हो। इसके परिणाम दिखने लगे हैं। पिछले नौ वर्षों में न केवल किसान आत्महत्याओं में कमी आई बल्कि कृषि बाजार के उदारीकरण से किसानों की आमदनी बढ़ी और कृषि उपजों का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया।

रमेश दूबे
लेखक केंद्रीय सचिवालय
में अधिकारी हैं।

मजबूत अर्थव्यवस्था से आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बन रहा है भारत

नरेंद्र मोदी जी 25 मई, 2023 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूर्ण कर लेंगे । इस लंबी अवधि के दौरान मोदीजी की सरकार ने आर्थिक नीति के मोर्चे पर अनगिनत साहसिक निर्णय लिए हैं। जिसकी वजह से भारत की गणना विश्व के अग्रिम और संभावना वाले देश के तौर पर की जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृतकाल के दौर में प्रवेश कर चुका है, हम ग्लोबल इकोनॉमी में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। भारत ने युनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है और ये मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की बेहद बड़ी सफलता है।

जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 2.6 फीसदी पर रहा था, आज इसे देखें तो ये बढ़कर 3.5 फीसदी पर आ चुका है।निश्चित रूप से आजादी के 75वें वर्ष में ये आंकड़ा देश का हौसला बढ़ाने का काम करता है। 2014 से लेकर अब तक देश के गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) कलेक्शन में 22 फीसदी की वृद्धिहुयी है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भारत सरकार का जो आर्थिक संकल्प है, ये आंकड़े उसे दर्शाते है।

भारत के इस अमृत काल में मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में कोई भूखा ना सोने पाए। आज सक्षम नेतृत्व की वजह से देश की 80 फीसदी जनसंख्या को 5 किलो चावल और एक किलोग्राम दाल मुहैया करने के संकल्प की पूर्ति हो रही है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास का लाभदेश के सभी नागरिकों को मिले। ओर इस आर्थिक विकास में देश के नागरिको की सहभागिता भी मोदी जी ने सुनिश्चित की है उदाहरण के तौर पर देश में जीएसटी का कलेक्शन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन ने सारे पुराने रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। विगत माह यह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पहला मौका है जब किसी महीने जीएसटी 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा है।

साथ ही एफडीआई इनफ्लो का असर वित्तीय वर्ष 2022 में 83 बिलियन डॉलर का रहा जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है साथ ही साथ मोदी सरकार की यह एक बड़ी उपलब्धि भी है।

तमाम राष्ट्रीय एजेंसियां और वित्तीय संस्थान भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी को स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में मोर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2022-23 में भारत की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। मोर्गन स्टेनली के अनुसार इसी के साथ एशिया की ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत और विश्व की ग्रोथ में 22 प्रतिशत रहेगी। मोर्गन स्टेनली ने यह भी कहा है की मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7 फीसदी औसतन रहने का अनुमान है जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।वर्ष 2014 से पहले, भारत 'फ्रैजाइल फाइव' देशों में से एक था, यह शब्द निवेश फर्म मॉर्गन स्टेनली ने ही गढ़ा गया था। आज हम उस श्रेणी से निकलकर विश्वकी 'फैबुलस फाइव' अर्थव्यवस्थाओं में सहभागी हो गए हैं । मॉर्गन स्टेनली के प्रबंध निदेशक श्री चेतन अह्या द्वारा वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर हाल ही में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी । अगले दस वर्षों में भारत की जीडीपी बढ़कर 8.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत विश्व के लिए आशा और विश्वास का केंद्र बन गया है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सरकार की प्राथमिकता में देश को उपभोक्ता से उत्पादक देश बनाने की तय की थी।इस हेतु मेक इन इंडिया समेत वोकल फ़ॉर लोकल एंड ग्लोबल जैसे कई अभियानों को चलाया गया। इसमें भारत ने उपलब्धि प्राप्त की जिससे निर्यात काफी बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022 के आंकड़ों को देखे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 421 मिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है . 'मेक इन इंडिया' और 'पी.एल.आई. स्कीम' के कारण वस्तुओं के निर्यात में 100 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ौतरी हुई। वर्ष 2013-14 में 312 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था और जो वर्ष 2021-22 में आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार 421 अरब डॉलर का रहा। साथ ही सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट 254 मिलियन डॉलर के आंकड़े को प्राप्त किया है।

भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जहाँ अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे विकसित देशों पर भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है वहीं भारत में मंदी की संभावना शून्य है। इंग्लैंड में मंदी की सबसे अधिक आशंका यानी 75 फीसदी है. वहीं न्यूजीलैंड 70 फीसदी आशंका के साथ दूसरे और अमेरिका 65 फीसदी के साथ तीसरे नंबर पर है। यहाँ तक की भारत की सबसे बड़ी चुनौती और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में भी मंदी आने की आशंका इस साल 12.5 फीसदी है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अगले तीन साल में भारत निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान है जहाँ गिरावट के आसार कम सबसे कम हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 9वर्षो के कार्यकाल में आर्थिक विकास की बदौलत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके कारण देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है । इसमें जी.एस.टी. लागू करने से हमारी कर व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि के साथ ही व्यापारी और आम लोगों को भी सहूलियत हुई। सभी गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसके बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि हुई। 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'पी.एल.आई. स्कीम', 'दीवालिया कानून', 'ईज आफ डूइंग बिजनैस', 'डिजिटलीकरण' जैसे सुधार कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल हैं। 'जनधन योजना' के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था से पूरा देश जुड़ गया है।

वर्ष 2014 तक मात्र 2.45 करोड़ बैंक खाते थे, लेकिन वित्तीय समावेश के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरूआत की गई और इस योजना के तहत 45.41 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इनमें 1,67,145.80 करोड़ रुपए जमा हैं । डिजिटलाइजेशन में आज विश्व का 40 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मोबाइल का चिप कभी हम दूसरे देशों से आयात करते थे, आज हम इसके उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं।

निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षो में भारत एक आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरा है जो सामूहिक कल्याण में विश्वास करता है।

अजय धवले
लेखक कॉर्पोरेट लॉयर हैं.
प्रतुस्त विचार निजी हैं.

मोदी सरकार के 9 वर्ष: जनजागरूकता से लेकर आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर युवा कल्याण, हर दिशा में मोदी सरकार ने छोड़ी छाप

आगामी 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी प्रचंड बहुमत से लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले वे 2014 में देश की जनता द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। इस प्रकार उन्हें बतौर प्रधानमंत्री अब कुल 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनकी करीब एक दशक की यह यात्रा बहुआयामी और बहुअर्थी रही है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे बिरले नेता हुए हैं जिनके पास एक दूर दृष्टि की संपदा रही। अर्थात् ऐसे नेता जो केवल भाषणों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नवाचार किया और नई लीक का निर्माण किया। कहा जा सकता है कि मोदी भी इसी क्रम में आते हैं। आरंभिक समय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर वर्तमान दौर के योगी आदित्यनाथ तक नवाचार की शृंखला रही है। जहां तक मोदी की बात है, मोदी को हम एक युगपत नेता की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात् ऐसे नेता जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद के भारत में जमीन आसमान का अंतर आया है। सत्ता में तो वे और अधिक पहले से रहे हैं। सत्ता की ही बात करें तो उनको 22 वर्ष हो गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2001 में दायित्व संभाला था। इसके बाद वे लगातार तीन बार मुख्यमंत्री चुने गए और जब राष्ट्र प्रमुख बने तब भी उनके दो कार्यकाल लगातार हुए हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह गौरवपूर्ण उपलब्धि पाने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। चूंकि अब केंद्र में उन्हें 9 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में एक आम नागरिक के तौर पर मन में इस जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है कि आखिर राष्ट्र निर्माण में मोदी का क्या और कितना योगदान है। नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत हैं जिनके हिस्से में सदा चुनौतियां ही आईं हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने गुजरात संभाला था तब 2001 में राज्य विनाशकारी भूकंप की विभीषिका झेल रहा था। उजड़े हुए राज्य को संवारने का बीड़ा उठाकर मोदी ने अपनी अलग ही पहचान बना ली। इसके बाद आगामी दोनों कार्यकाल में उन्होंने गुजरात में निवेश सम्मेलन सफलतापूर्वक करवाए और गुजरात में व्यापक विकास कार्य करवाकर जल्द ही राज्य को देश के उन्नत, विकसित एवं प्रगतिशील राज्यों की कतार में ला खड़ा किया। ठीक ऐसा ही प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में भी हुआ। जब 2014 में उन्होंने पद संभाला था तब देश में संप्रग

सरकार के कार्यकाल की कारगुजारियों के काले निशान साफ देखे जा सकते थे। जनता आतंकी हमलों की दहशत से त्रस्त थी। देश आर्थिक घोटालों से त्रस्त था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के ठीक पहले तक मनमोहन सिंह की सरकार में घोटालों का अंबार लग गया था। कॉमनवेल्थ घोटाला, टेलीकॉम घोटाला जो कि टूजी स्पेकट्रम घोटाले के नाम से जाना जाता है, कोल घोटाला जैसे कई घोटालों ने देश को खोखला कर दिया था। जहां तहां आबादी भरे इलाकों में होने वाले आतंकी हमलों से देश सिहर गया था। कांग्रेस की सरकार के इस लचर कार्यकाल में देश की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है। इस पर भी केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल किसी एक परिवार के हाथ में होने से देश की तो पूरी कमर ही टूट गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी के सामने देश को इस बदहाली से उबारने की चुनौती थी। शपथ ग्रहण करने के बाद तुरंत बाद ही मोदी अपने देश निर्माण व सुधार के मिशन में जुट गए। संसद में पहली बार प्रवेश करते ही उन्होंने जिस प्रकार झुककर, सांष्टांग लेटकर सदन को प्रणाम किया था, उससे ही देश को यह संकेत मिल गया कि देश अब सही हाथों में है। 2015 में मोदी ने नवाचार आरंभ किया। गांधी जयंती से उन्होंने देश में स्वच्छता मिशन के रूप में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। बीते 9 वर्षों में यह एक विराट जन आंदोलन व जन जागरूकता की जीवन शैली बन चुका है। देश भर के शहर, गांव, कस्बे अब स्वयं को साफ रखने की होड़ में हैं और इसी बहाने देश स्वच्छ हो रहा है। हर साल स्वच्छता के पुरस्कार वितरित किए जाने का ध्येय भी इस क्रम को, इस लय को बनाए रखना है। मोदी ने उसी दौरान जन धन योजना लागू की और समाज के निम्न वर्ग के तबके को बैंकिंग सेक्टर की मुख्य धारा से जोड़ा।

इसी दौरान सरकार ने देश में डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया। स्टार्ट अप इंडिया के तहत देश में स्वरोजगार के अवसर खुले और मुद्रा योजना के तहत लोन मिलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोग स्वयं के घर का सपना साकार कर सके जिसमें उन्हें ढाई लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली। अब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी देश का युवा स्व रोजगार के आयाम छू रहा है। वर्ष 2016 में जब उरी आतंकी हमला हुआ तब देश भर में इसे लेकर गुस्सा था। मोदी सरकार की कुशल व त्वरित कार्यशैली के चलते भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसिक व गौरवशाली ऑपरेशन को साकार किया। इस घटना के बाद देश ही नहीं, दुनिया में भी मोदी की छबि की स्वीकार्यता बढ़ी।

इसी साल उन्होंने नोटबंदी जैसा बड़ा आर्थिक सुधार करके सबको चौंका दिया और काले धन के माफियाओं की कमर तोड़ दी। 2017 में जीएसटी को लागू करके एक बड़ा व्यापारिक सुधार किया। इसी समय अमेरिका में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिकाआमंत्रित किया। मोदी व ट्रंप की गले मिलने वाली तस्वीर पर पूरी दुनिया की नज़रें जम गईं। चूंकि मोदी एक दशक बाद अमेरिका की यात्रा पर थे और इसे उनकी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा गया क्योंकि अमेरिका ने ही उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था और स्वयं ही आमंत्रित किया।

इससे मोदी की छबि ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत हुई। 2018 में मोदी ने तीन तलाक जैसी इस्लामिक कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया और संसद के दोनों सदनों यह पारित होकर कानून बना। मोदी सरकार ने ही देश में आधार कार्ड व पैन कार्ड को लिंक करने का अभियान शुरू जिससे हर नागरिक की पहचान सुनिश्चित हो गई। मोबाइल की फर्जी सिम,फर्जी बैंक खातों पर इससे अंकुश लगाने में सफलता मिली। वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक सफलता पाई। इसमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का अदालती फैसला शामिल है। इसी साल पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में 45 जवानों के बलिदान को लेकर आक्रोश था और प्रतिशोध की प्रबल उत्कंठा थी। सरकार के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने 12 दिन बाद ही बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने तबाह कर दिये और जवानों की शहादत का बदला ले लिया।

वर्ष 2020 फिर से बड़ी चुनौती लेकर आया जब कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। खतरे को भांपते हुए मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन लगाया और एक बड़ी आबादी को घातक वायरस की चपेट में आने से बचा लिया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस दौरान भी उन्हें बहुत परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। संक्रमण का असर कम होने पर पाबंदियों के साथ देश में चरणबद्ध रूप से अनलॉक की शुरुआत हुई और अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। जब लॉकडाउन लगा था तब केंद्र सरकार ने जनता के लिए कई कल्याण कारी योजनाएं चलाईं। जन धन खातों में हर माह पैसे जमा करवाना, पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 2 हजार रुपए की किश्त जमा करवाना, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई एवं जनरल प्रमोशन देना, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को 75 फीसदी अग्रिम राशि का भुगतान किया जाना व आयकर सहित अन्य मामलों में समय-सीमा बढ़ाई जाना इनमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। सरकार ने एक से अधिक बार आर्थिक पैकेज की घोषणा की और गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। इसी साल सरकार ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निमार्ण कार्य का भूमिपूजन करके यह साबित कर दिया कि उनके लिए जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का नाम महज चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी आराधना मुख्य ध्येय है। जनवरी 2021 में देश ने स्वदेशी वैक्सीन के रूप में बड़ी सफलता हासिल की और कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कोरोना की दूसरी प्रलंयकारी लहर में देश में बहुत जनहानि हुई लेकिन लहर के बाद देश में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी और अब हमारा देश 100 करोड़ से अधिक डोज देने वाला दुनिया का अनोखा राष्ट्र बन चुका है। 2022 से 2023 के बीच मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों को लेकर भी नवाचार किया है। अब पूर्ववर्ती सरकार की तरह अयोग्य एवं असंगत लोगों को गलत पुरस्कार नहीं दिए जाते बल्कि समाज के जमीन से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कई क्षेत्रों में जन जागरूकता की मिसाल कायम की है। कहा जा सकता है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है और आम आदमी का पूरा ध्यान रख रही है।

यह बात अलग है कि विपक्षी दलों ने कोरोना काल के पहले और बाद भी सरकार के अच्छे कार्यों से दुर्भावनावश दुष्प्रचार किया और जनता को गुमराह करने की कोशिश की। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में विपक्षी दलों ने हिंसा व नफरत का माहौल बनाया। शाहीन बाग जैसे कुत्सित उदाहरण सामने आए। दिलली के दंगे और बंगाल की हिंसा को कौन भूल सकता है। 26 जनवरी, 2021 का दिन देश के लिए काला दिन था जब तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों व असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर बेजा कब्जा कर लिया। इन सब घटनाओं ये यह तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इससे शहरी नक्सलियों के पेट में दर्द हो रहा है। अब तो भारत के खिलाफ सारी साजिशें विदेशों से तय होने लगी हैं। टूलकिट एक बड़ा हथकंडा बनकर सामने आया है। विपक्षी दलों के नेता, देश विरोधी मानसिकता वाले पत्रकार और फिल्म अभिनेता भी इस दुष्चक्र का हिस्सा बने हुए हैं।

कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी भ्रम का माहौल बनाया गया लेकिन केंद्र सरकार ने व्यर्थ के विवादों पर ध्यान न देते हुए अपना विकास रथ जारी रखा। नतीजा आज सामने है कि आज भारत दुनिया के प्रगतिशील व उन्नत राष्ट्रों में शुमार है। निश्चित ही 2014 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग में कई चुनौतियां आईं लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने लक्ष्य, मिशन, विजन, कर्म और विकास यज्ञ से डिगी नहीं है। उम्मीद है अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार को जनता का पूरा साथ मिलेगा।

नवोदित सक्तावत

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं.
प्रस्तुत विचार निजी हैं.

विकसित और नए भारत की नींव

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में नौ वर्ष पूरे किए। सन्योग है कि नौंवी वर्षगांठ के ठीक पहले पापुआ न्यू गिनी ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। गवर्नर जनरल सर बाब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहु दिया। फिजी के प्रधानमंत्री सितीवेनी राबुका ने 'कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। चुनिंदागैर फिजी नागरिकों को यह सम्मान दिया गया है। नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक दर्जन सम्मान मिल चुके है। देश विदेश में मोदी मोदी की गूंज होती है। जबकि इस अवधि में दो वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप रहा। इसने दुनिया के विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ। इससे अभी संभलने का प्रयास चल रहा था तभी रूस यूक्रेन संकट सामने आ गया। इन सभी कारणों से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका व यूरोप के विकसित देशों में कई दशक कर बाद ऐसी मंहगाई देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो इस अवधि में दुनिया की सबसे बड़ी नि:शुल्क राहत वितरण योजना का संचालन किया। दुनिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क टीकाकरण अभियान चलाया। इसके अलावा राहत के अनेक कार्य किये गए। जाहिर है कि परिस्थितियां प्रतिकूल रही है। दुनिया का कोई देश इससे बचा नहीं है। किंतु भारत का विपक्ष नकारात्मक राजनीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। निष्पक्षता के नाम पर नकारात्मक प्रचार करने वाले पत्रकार भी इसमें शामिल है। वह बता रहे है कि नौ वर्षो में महंगाई की दर सर्वाधिक है किंतु उनके विश्लेषण में दुनिया की परिस्थिति शामिल नहीं है। यूपीए सरकार तेल उत्पादक देशों व कम्पनियों का कई लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई थी। इसकी भरपाई भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। इन नौ वर्षों में अनेक संवेदनशील समस्याओं का समाधान हुआ। यह सभी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण ही संभव हुआ। यदि कोई अन्य सरकार होती तो इन मसलों पर चर्चा तक मुनासिब ना होती। कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता श्री रामजन्म भूमि सुनवाई को टालने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे थे। श्री रामजन्म भूमि का विवाद पांच शताब्दी पुराना था। कहा जा रहा था कि दोनों पक्ष सहमति से इसका समाधान निकालें या कोर्ट का फैसला माने। सहमति से समाधान असंभव था। मंदिर के विरोध में बाकायदा एक्शन कमेटी बनी थी।

अपने को सेक्युलर घोषित करने वाले भी मंदिर निर्माण के विरोधी थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में शीघ्र सुनवाई का मार्ग प्रशस्त किया। इससे सदियों से लंबित समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। 26 मई को मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तीन तलाक पर प्रतिबंध भी नरेंद्र मोदी सरकार के कारण संभव हुआ। अनेक मुस्लिम देश इस पर रोक लगा चुके है लेकिन भारत में रोक की बात को ही साम्प्रदायिक करार दिया जाता था लेकिन मोदी सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की। उसने पहल की, अंततः तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। अनुच्छेद 370 और 35 A का विरोध करना भी साम्प्रदायिकता माना जाता था। सेक्युलर दिखने के लिए इन अलगाववादी प्रावधानों का समर्थन जरूरी था। संसद में इस पर चली बहस से यह प्रमाणित भी हुआ। इसके हटने पर गम्भीर परिणाम की चेतावनी तक दी गई लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको हटा कर ही दम लिया। देश में सत्तर वर्ष बाद एक विधान एक निशान लागू हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है। इसलिए देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने अपनी दूरदर्शी नीतियों, समर्पण और टीम इंडिया की भावना के साथ देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है।

सरकार के प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण व राष्ट्रीय हित के अनुरूप है। मोदी ने दशकों से लंबित फैसलों को लागू किया। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में दुनिया को चकित और प्रेरित करने का सामर्थ्य है। लेकिन इसके लिए पहले देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। बीस लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सहारे भारत आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई गति मिली है। सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन किया गया। आपदा के इस दौर में उत्पीड़ित लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके विरोध में जम कर हंगामा हुआ था। हंगामे के समर्थन करने वाले दलों व इसे लागू ना करने वाली राज्य सरकारों को शर्मिंदा होना चाहिए।

आजादी के बाद सात दशकों में देश के केवल साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे। लेकिन पिछले पिछले महीनों में ही साढ़े चार करोड़ घरों को साफ पानी कनेक्शन दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान लागू की गई। इसके दायरे में पचास करोड़ लोग है। नौ सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। रिकॉर्ड सैटेलाइट प्रक्षेपित किये जा रहे हैं। रिकॉर्ड सड़कें बनाई जा हैं। दशकों से लंबित अनेक योजनाएं पूरी की गई। अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं।

पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। स्वरोजगार के लिए मुद्रा बैंक ने बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया। स्वनिधि योजना से भी गरीब व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। कोरोना काल में अस्सी करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन की व्यवस्था की गई। जन औषधी दवा केन्द्र की संख्या अस्सी से बढ़कर पांच हजार हो गई। करीब सवा सौ नये मेडिकल कालेज खुले है। यूपीए के दस वर्ष में भारतीय रेल ने मात्र चार सौ तेरह रेल रोड ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया। मोदी सरकार ने इससे तीन गुना अधिक निर्माण किया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पन्द्रह करोड़ से ज्यादा लाभार्थी है। यह दुनिया की सबसे सस्ती योजना है। बिजली उत्पादन चालीस प्रतिशत वृद्धि हुई। सोलर ऊर्जा में आठ गुना वृद्धि हुई। फसल बीमा योजना का लाभ पहले पचास प्रतिशत नुकसान पर मिलता था। अब किसान को तैतीस प्रतिशत पर भी मिल जाता है। युरिया को नीम कोटेड किया कलाबाजारी खत्म हुई। देश मे युरिया की कोई कमी नहीं है। बारह करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से ऋण मिला। इतने ही किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। पिछली सरकारों के समय बावन सेटेलाईट लाँच किये थे। मोदी सरकार ने अब तक देशी विदेशी करीब तीन सौ सेटेलाईट लाँच कर चुकी हैं। यूपीए के समय ग्रामीण सडक से जुडी बस्ती मात्र पचपन प्रतिशत थी। अब करीब 95 प्रतिशत हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार ने चालीस करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए। पहले ये लोग बैंकिंग सेवा से वंचित थे। आयुष्मान, उज्ज्वला और निर्धन आवास योजनाएं संचालित की गई। देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। भाजपा सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाई। आठ करोड़ गैस कनेक्शन दिए। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि योजनाओं के एक रुपये में पन्द्रह पैसा गरीबों तक पहुंचता था। लेकिन वे बस कहकर ही रह गए, समाधान की दिशा में कुछ नहीं किया। समाधान नरेंद्र मोदी ने किया है। आज पूरा पैसा सीधे लोगों के खातों में पहुंच रहा है।

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं.
प्रस्तुत विचार निजी हैं.